सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने के लिए शर्तें

983. **श्री बालकवि बैरागी:**
श्रीमती वीणा वर्मा:
श्री राजूभाई ए० परमार:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिषेध संधि पर हस्ताक्षर करनें के लिए कतिपय शर्तें प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हां, तो व्यक्त की गई स्टीक शर्तें कौन-कौन सी हैं;

(ग) अमरीका तथा अन्य परमाणु शक्तियों की उन पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) संधि पर कब तक हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है; और

(ङ) भारत द्वारा संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के कारण इसे क्या लाभ और हानि होगी?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (ङ) सीटीबीटी पर सरकार की स्थिति संसद के समक्ष रखी गई है। 15 दिसम्बर, 1998 को प्रधान मंत्री ने कहा था कि 'भारत अब सीटीबीटी सहित बहुत से मसलों पर प्रमुख वार्ताकारों के साथ बातचीत कर रहा है। हम इन बातचीतों को एक सफल निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं, ताकि सीटीबीटी को सितम्बर, 1999 तक प्रवृत्त किया जा सके। हमें आशा है कि सीटीबीटी के अनुच्छेद चौदह में बताए गए अन्य देश बिना किसी शर्त के संधि का पालन करेंगे। हम बातचीतों को सफल निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए हमारे प्रमुख वार्ताकारों द्वारा सकारात्मक वातावरण तैयार करना एक आवश्यक कार्य है। हमारा वक्तव्य सकारात्मक प्रत्युत्तर दर्शाता है तथा एक सकारात्मक कदम है।'

Observations of UNIDIR

984. SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI AKHILESH DAS:
SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR) in its report following the Geneva Conference of September last, had observed that South Asian nuclear neighbours had neither enhanced their own security nor international status by conducting the series of tests in May, 1998;

(b) if so, what other main observations and recommendations were made in the report for improving the global security environment; and

(c) what steps, if any, have been are being taken by Government in the light thereof?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI JASWANT SINGH): (a) and (b) The Geneva based United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR) organised an off-the-record meeting of academics, non-governmental organisations and government representatives on *"The Implications of South Asia's Nuclear Tests for the Non-Proliferation and Disarmament Regimes"* in Geneva from 7-8 September 1998. The Report of this Conference summarises the discussions held and various policy options suggested during the meeting by the participants in their personal capacities. Not all points in the report received the support of all participants, nor did their inclusion imply endorsement by the UNIDIR or any other body. The summary of the Report, included proposals relating to prevention of war, in particular nuclear war, saving the non proliferation and nuclear arms control regimes and coping with effects on regional tensions, especially in the Middle East. As the Report itself notes, these proposals were not consistent. The Report was not conclusive in terms of observations and recommendations.

(c) Government's decisions relating to our nuclear policy will continue to be taken in accordance with our own assessment of national security requirements.